प्रस्ताव

62 मृत्यु दंड। पहल संविधि (कानून)।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश

अटार्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया

- हत्या के दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए अधिकतम दंड के रूप में मृत्यु दंड को निरस्त करता है और उसके स्थान पर पैरोल की संभावना से विहीन आजीवन कारावास लागू करता है।
- पहले ही मृत्यु दंड के भागी घोषित हो चुके व्यक्तियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।
- यह कहता है कि हत्या के दोषी पाए गए एवं पैरोल की संभावना से विहीन आजीवन कारावास भोग रहे व्यक्तियों को जेल में रहने के दौरान, सुधार एवं पुनर्वास विभाग द्वारा यथा विहित रूप से कार्य करना होगा।
- आजीवन बंदी के वेतन के अंश को बढ़ाता है जो पीड़ित की क्षतिपूर्ति पर लागू किया जा सकता है।

विधायी विश्लेषक के निवल राज्य एवं स्थानीय सरकार वित्तीय प्रभाव के आकलन का सारांश:

- कुछ ही वर्षों के अंदर, हत्या के अभियोगों, मृत्यु दंड को कानूनी चुनौतियों, एवं जेलों से संबंधित राज्य व काउंटी लागतों में लगभग $150 मिलियन प्रतिवर्ष की निवल जारी कटौती। इस आकलन में दसियों मिलियन डॉलर की घट-बढ़ हो सकती है जो कई कारकों पर निर्भर है।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

हत्या के लिए मृत्यु दंड की सज़ा

पहली डिग्री की हत्या को आम तौर पर किसी मानव को मारने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो (1) जानबूझकर और पूर्वचिन्तित है या (2) उस समय होती है जब कुछ अन्य अपराध किए जा रहे हों जैसे कि अपहरण। यह न्यूनतम 25 साल बाद राज्य पैरोल बोर्ड द्वारा छोड़े जाने की संभावना के साथ राज्य के किसी कारावास में आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय है। हालांकि, मौजूदा राज्य कानून पहली डिग्री की हत्या को मृत्यु दंड या पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास से दंडनीय बनाते हैं जब अपराध की "विशेष परिस्थितियों" पर आरोप लगाया जाता है और अदालत में साबित किया जाता है। मौजूदा राज्य कानून ऐसी विशेष परिस्थितियों की पहचान करता है जिनमें आरोप लगाया जा सकता है, जैसे कि वे मामले जिनमें हत्या को वित्तीय लाभ के लिए किया गया था या जब एक से अधिक हत्याएं की गईं थीं।

मृत्यु दंड की कार्यवाहियाँ

मृत्यु दंड के मुकदमों में दो चरण हो सकते हैं। पहला चरण हत्या के मुकदमे का होता है जिसमें अभियोक्ता मृत्यु दंड की माँग करता है जिसमें यह निर्धारित किया जाना होता है कि क्या प्रतिवादी हत्या का दोषी है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों का निर्धारण किया जाता है। यदि प्रतिवादी दोषी पाया जाता है और कोई विशेष परिस्थिति सिद्ध की जाती है, तो दूसरे चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि क्या मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए या परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। कत्ल के इन मुकदमों के परिणामस्वरूप राज्य के मुकदमा अदालतों को लागतें उठानी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, काउंटियाँ इन व्यक्तियों के अभियोजन के साथ-साथ इन व्यक्तियों के बचाव के लिए लागतें वहन करती हैं जो कानून प्रतिनिधित्व का खर्च नहीं उठा सकते। California में 1978 में वर्तमान मृत्यु दंड कानून को लागू करने के बाद से, 930 व्यक्तियों को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है। हाल के वर्षों में, औसतन लगभग 20 व्यक्तियों ने वार्षिक रूप से मृत्यु दंड प्राप्त किया है।

मृत्यु दंडों के प्रति कानूनी चुनौतियाँ। वर्तमान राज्य कानून के तहत, मृत्यु दंड के फैसले के खिलाफ स्वतः ही California की सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। इन "प्रत्यक्ष अपीलों" में बचाव पक्ष के वकील तर्क देते हैं कि मुकदमे के दौरान राज्य के कानून या संघीय संवैधानिक कानून का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि सबूत को अनुचित तरीके से शामिल किया जाना या मुकदमे से बाहर रखना। यदि California की सुप्रीम कोर्ट अपराध और मृत्यु दंड की पुष्टि करता है, तो प्रतिवादी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए माँग कर सकता है। प्रत्यक्ष अपील के अलावा, मृत्यु दंड के मामलों में आमतौर पर, राज्य और संघीय अदालतों, दोनों में व्यापक कानूनी चुनौतियाँ शामिल होती हैं। ये चुनौतियाँ

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

जिन्हें आमतौर पर "बंदी प्रत्यक्षीकरण" ("habeas corpus") याचिकाएं कहा जाता है, में मामले के वे कारक सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष अपीलों में विचार किए जाने वाले कारकों से भिन्न होते हैं (जैसे कि यह दावा कि प्रतिवादी का वकील प्रभावहीन था)। ये सभी कानूनी चुनौतियाँ—जिनका किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलने के समय से व्यक्ति द्वारा सभी राज्य और संघीय कानूनी चुनौती कार्रवाइयाँ पूरा किए जाने तक मूल्यांकन किया जाता है—California में पूरा होने में कुछ दशकों का समय ले सकती हैं।

राज्य वर्तमान में उन कानूनी चुनौतियों पर वार्षिक रूप से लगभग $55 मिलियन खर्च करता है जिनके बाद मृत्यु दंड दिया जाता है। यह निधि California की सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ राज्य के न्याय विभाग द्वारा नियुक्त उन वकीलों की सहायता करती है जो अदालतों में मामलों को चुनौती देने के समय मृत्यु दंड को बरकरार रखने के लिए माँग करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह निधि उन विभिन्न राज्य एजेंसियों की भी सहायता करती है जिन्हें उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम सौंपा जाता है जिन्हें मृत्यु दंड मिला है लेकिन जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च नहीं उठा सकते।

मृत्यु दंड का क्रियान्वयन

मृत्यु दंड पाए हुए कैदियों का आवास। अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार 1978 के बाद से मृत्यु दंड की सज़ा पाए हुए 930 व्यक्तियों में से 15 को मृत्यु दंड दिया गया है, 103 मृत्यु दंड दिए जाने से पहले मर चुके हैं, 64 की सज़ा अदालतों ने कम कर दी है और 748 मृत्यु की सज़ा के साथ राज्य के जेल में हैं। 748 मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों में से एक बड़ी संख्या प्रत्यक्ष अपील या हैबियस कॉरपस पटीशन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। मृत्युदंड प्राप्त पुरुष कैदियों को आमतौर पर San Quentin राज्य जेल (मौत की कगार पर) में रखे जाने की ज़रूरत होति है, जबकि मृत्युदंड प्राप्त महिला कैदियों को केन्द्रीय California की Chowchilla में महिला सुविधा में रखा जाता है। राज्य में वर्तमान में विभिन्न सुरक्षा नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनके परिणामस्वरूप इन कैदियों के लिए सुरक्षा की लागत में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए, मृत्यु दंड के तहत कैदियों को आमतौर पर हथकड़ी पहनायी जाती है और उनके प्रकोष्ठों के बाहर उनके साथ एक या दो अधिकारियों को हर समय साथ रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकाँश अपराधियों के विपरीत, मृत्युदंड पाए हुए कैदियों को वर्तमान में अलग कोठरियों में रखना अपेक्षित है।

अदालतों द्वारा वर्तमान में रोके गए मृत्यु दंड। राज्य मृत्यु दंड की सज़ा पाए हुए कैदियों के लिए घातक इंजेक्शन का प्रयोग करता है। राज्य के घातक इंजेक्शन की प्रक्रियाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों के कारण, 2006 से मृत्यु दंड नहीं दिया गया है। राज्य वर्तमान में मृत्यु दंडों के फिर से आरंभ होने की कार्यविधियाँ विकसित करने की प्रक्रिया में है।

प्रस्ताव

पहली डिग्री की हत्या के लिए मृत्यु दंड समाप्त करना। इस विधेयक के तहत, पहली डिग्री की हत्या के लिए राज्य द्वारा किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं सुनाया जा सकता। इसकी बजाए, अधिक गंभीर उपलब्ध दंड राज्य परोल बोर्ड द्वारा छोड़े जाने की संभावना के बिना आजीवन कारावास होगा। (इस मतपत्र पर एक अन्य विधेयक है—प्रस्ताव 66—जो मृत्यु दंड को बनाए रखेगा लेकिन जिसमें उस समय में कमी करने की माँग की गई है जो मृत्यु दंड में लगता है।)

मृत्यु दंड के कैदियों को परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की पुनः सज़ा देना। यह विधेयक यह भी बताता है वर्तमान में मृत्यु दंड की सज़ा पाने वाले अपराधियों को फाँसी नहीं दी जाएगी और इसके बजाय उनको पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह विधेयक California की सुप्रीम कोर्ट को अपनी सभी मौजूदा मृत्यु दंड प्रत्यक्ष अपीलों और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को राज्य की अपीलीय या सामान्य अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये अदालतें मृत्यु दंड से असंबद्ध किन्हीं शेष मुद्दों का समाधान करेंगी—जैसे निर्दोष होने के दावे।

कैदी का कार्य और अपराध के शिकार को भुगतान संबंधी अपेक्षाएं। राज्य के वर्तमान कानून की आमतौर पर आवश्यकता है कि हत्यारों सहित कैदी जेल में रहने के दौरान काम करें। राज्य जेल के नियम इन काम की आवश्यकताओं के लिए कुछ अपवादों को भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि वे कैदी जो काम के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा, अदालतें कैदियों द्वारा अपराध के पीड़ितों को भुगतान करने को आवश्यक बना सकती हैं। यह

प्रस्ताव 62 के पूर्ण पाठ्य के लिए, देखें पृष्ठ 156।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

विधेयक बताता है कि हत्या का दोषी पाए गए हर व्यक्ति को जेल में रहने के दौरान काम करना होगा, और राज्य के नियमों के अधीन अपराध के पीड़ितों को देय किसी ऋण में भुगतान के लिए अपने वेतन में कटौती करानी होगी। क्योंकि यह विधेयक राज्य के नियमों को नहीं बदलता है, कैदियों के जेल में काम करने की आवश्यकताओं से संबंधित मौजूदा प्रथाओं में जरूरी रूप से बदला नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त, विधेयक उस अधिकतम धनराशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करता है जिसे अपराध के शिकार को देय किन्हीं ऋणों के लिए परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सज़ा पाए हुए कैदियों की मज़दूरी से काटा जा सकता है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिन्हें विधेयक के अंतर्गत परोल की संभावना के बिना मृत्युदंड की बजाए आजीवन कारावास की फिर से सज़ा दी जाती है।

राजस्व सम्बन्धी प्रभाव

इस विधेयक के राज्य और स्थानीय सरकारों पर अनेकों वित्तीय प्रभाव होंगे। विधेयक के प्रमुख वित्तीय प्रभावों पर चर्चा नीचे की गई है।

हत्या के मुकदमे

अदालत की कार्यवाही। इस विधेयक के कारण कुछ हत्या के मामलों से संबंधित, जो अन्यथा वर्तमान कानून के तहत मृत्यु दंड के लिए पात्र होते, राज्य और काउंटी के साथ जुड़ी लागतें कम होंगी। अगर मृत्यु दंड दो प्राथमिक कारणों से एक विकल्प नहीं था तो ये मामले आम तौर पर कम खर्चीले होंगे। प्रथम, मुकदमों की अवधि को छोटा किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब यह निर्धारित करने के लिए कोई अलग चरण नहीं होगा कि क्या मृत्यु दंड दिया गया है। हत्या के मुकदमों के अन्य पहलुओं को भी छोटा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मुकदमों के जूरी चयन के समय को छोटा किया जा सकता है क्योंकि अब उन संभावित जूरी सदस्यों को हटाना आवश्यक नहीं होगा जो मृत्यु दंड को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, मृत्यु दंड की समाप्ति से कुछ मुकदमों के लिए अभियोजन पक्ष और सार्वजनिक रक्षकों के लिए काउंटी द्वारा वहन की जाने वाली लागत में कमी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एजेंसियाँ आमतौर पर ऐसे मामलों में, जहां मृत्यु दंड की मांग की जाती है, अधिक वकीलों का उपयोग करती हैं और ऐसे मामलों में जांच करने में और सज़ा देने के चरण के लिए अन्य तैयारियों संबंधित ज्यादा खर्च वहन करती हैं।

काउंटी जेल। इस विधेयक का प्रभाव हत्या के मुकदमों पर पड़ने के कारण काउंटी जेलों की लागत को भी कम किया जा सकता है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग, विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहाँ उनको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आमतौर मुकदमा पूरा होने तक और सजाए सुनाए जाने तक काउंटी जेलों में रहते हैं। हत्या के कुछ मामले मृत्यु दंड समाप्त करने के कारण छोटे हो जाते हैं, इसलिए हत्या के दोषसिद्ध व्यक्तियों को उससे जल्दी राज्य के जेल में भेजा जाएगा जितना उन्हें अन्यथा भेजा जाता। इस तरह के परिणाम से काउंटी जेल की लागत में कमी होगी और राज्य की जेल की लागत में वृद्धि होगी।

हत्या के मुकदमों से संबंधित प्रभावों का सार। कुल मिलाकर, यह विधेयक राज्य-व्यापी आधार पर हत्या के मुकदमों में अनेक दसियों मिलियन डॉलरों का राज्य और काउंटी का वार्षिक लागतों कम कर सकता है। वास्तविक कटौती मृत्यु दंड के मुकदमों, जो इस विधेयक की अभाव में अन्यथा घटित हुए होते, सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, कटौती की मात्रा को आंशिक रूप से उस हद तक ऑफसेट किया जा सकता है जिस तक मृत्यु दंड की समाप्ति ने हत्या के कुछ मामलों में कम सजा के बदले में अपराधी ठहराने के लिए प्रोत्साहन राशि में कमी हुई है। अगर दलील समझौतों के माध्यम से समाधान के बजाय अतिरिक्त मामले अदालतों में जाते, तो अदालतों, अभियोजन, और बचाव पक्ष के वकीलों का समर्थन करने के लिए और साथ ही काउंटी की जेलों का समर्थन करने के लिए राज्य और काउंटियों को अधिक लागतें झेलनी पड़ेंगी। यह किस सीमा तक होगी, यह अज्ञात है। अधिकाँश मामलों में, राज्य और देश उपर्युक्त लागत कटौतियों के परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों को संभावित रूप से अन्य अदालत और कानून प्रवर्तन कार्यकलापों के लिए भेजेंगे।

मृत्यु दंडों के प्रति कानूनी चुनौतियाँ

समय के साथ, इस विधेयक से California की सुप्रीम कोर्ट द्वारा और मृत्यु दंड के लिए कानूनी चुणौतियों में भाग लेने वाली राज्य की एजेंसियों के द्वारा राज्य पर आने वाले खर्चे कम होंगे। ये लागतों में कमी सालाना $55 मिलियन तक

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

पहुंच जाएगी। हालांकि, ये लागतों में कमी के कम समय में आंशिक रूप से ऑफसेट किए जाने की संभावना है क्योंकि शायद खर्चे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अदालतें उन कैदियों के बारे में, जिनको पहले से मृत्यु दंड दिया जा चुका, सभी मामलों का समाधान न कर लें। लंबे समय में, अपेक्षाकृत राज्य और स्थानीय लागत कम होगी - संभवतः सालाना कुछ मिलियन डॉलर - पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा प्राप्त करने वाले अतिरिक्त अपराधियों से अपील की सुनवाई के लिए।

राजकीय जेलें

मृत्यु दंड की समाप्ति से राज्य की जेल लागत पर अलग-अलग तरीकों से प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ, इसकी समाप्ति से कुछ जेलों में ज्यादा आबादी और उच्च लागत होगी क्योंकि पूर्व में मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वर्तमान में मृत्यु दंड पर कैदियों द्वारा बिताए गए समय की लंबाई को देखते हुए, इन लागतों के ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ये अतिरिक्त लागतों के संभावित रूप से मृत्यु दंड प्राप्त सैंकड़ों कैदियों को जेल में न रखने से लागतों में कमी से ज्यादा होंगी। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को जेल में रखना पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को जेल में रखने की तुलना में अधिक महंगा होता है, क्योंकि मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को जेल में रखने के और उनकी निगरानी करने के लिए उच्च सुरक्षा विधेयक इस्तेमाल किए जाते हैं।

इन वित्तीय प्रभावों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम-स्वरूप राज्य की जेल प्रणाली के संचालन के लिए राज्य को सालाना दसियों मिलियन डॉलर की बच्चतें होने की संभावना है। बहरहाल, ये बचतें उन मृत्यु दंडों की दर के आधार पर अधिक या कम हो सकती हैं जो अन्यथा दे दिए जाते।

अन्य वित्तीय प्रभाव

जेल का निर्माण। यह विधेयक मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की बढ़ी हुई संख्या को जेल में रखने से संबंधित भविष्य की सुविधा लागतों से बचने के लिए राज्य को अनुमति देकर भविष्य की जेल निर्माण लागतों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी किसी भी बचत की सीमा सजायाफ्ता कैदियों की भविष्य की जनसंख्या में वृद्धि, राज्य द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को भविष्य में कैद में रखने के तरीके के चयन, और सामान्य जेल आबादी में भविष्य में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करती है।

हत्या की दर पर प्रभाव। California में मृत्यु दंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का हत्या की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की हद तक, यह विधेयक राज्य और स्थानीय सरकार के आपराधिक न्याय खर्चों को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, अज्ञात है और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

वित्तीय प्रभावों का सारांश

कुल मिलाकर हमारा यह अनुमान है कि यह विधेयक हत्या के मुकदमों, मृत्यु दंड के प्रति कानूनी चुनौतियों और जेलों से संबंधित निवल राज्य और काउंटी की लागतों को कम करेगा। ये घटी हुई लागतें संभवतया कुछ वर्षों के भीतर वार्षिक रूप से लगभग $150 मिलियन होंगी। यह लागतों में कमी दसियों मिलियन डॉलर कम या ज़्यादा हो सकती है जो कई कारकों पर निर्भर है।

इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए प्राथमिक रूप से गठित समितियों की सूची के लिए *http://www.sos.ca.gov/measure-contributions* पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ता देखने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html* पर जाएं।